

उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संभावना पर एक वैचारिक अध्ययन

A conceptual study on the feasibility of National Education Policy 2020 on Higher Education

दलीप रैना¹ एवं सरिता यादव²

Dalip Raina¹ and Sarita Yadav²

^{1,2}Shri Vishwakarma Skill University, Palwal, Haryana

¹dalip.raina@svsu.ac.in, ²yadav.sarry@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18556704>

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के साथ भारत की शैक्षिक प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप प्रणाली को पूरी तरह से नया स्वरूप देना है। यह शोध पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदुओं, लक्ष्यों और संभावित प्रभावों की जांच करता है। नीति का उद्देश्य भारत को दुनिया भर में ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अधिक व्यापक, अनुकूलनीय और बहु-विषयक शैक्षिक ढांचा प्रदान करना है। प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षा नीति की ताकत, कार्यान्वयन की संभावनाओं और समस्याओं की पूरी तरह से जांच की गई है, जो कार्यक्रम के महत्वाकांक्षी उद्देश्य को साकार करने के लिए हितधारक जुड़ाव, कुशल शासन और रचनात्मक सोच के महत्व पर भी जोर देती है। शिक्षा नीति सतत विकास लक्ष्यों (SDG) जैसे वैश्विक शिक्षा एजेंडा को प्राप्त करने में कैसे उपयोगी है एवं समावेशी और सतत विकास के द्वार खोलते हुए भारतीय शिक्षा में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने में कैसे मदद कर सकती है।

Abstract

There has been a turning point in the evolution of India's educational system with the National Education Policy (NEP) 2020, which aims to completely redesign the system to suit the needs of the 21st century. This research paper examines key points, goals, and potential impacts of National Education Policy 2020. The policy aims to provide a more comprehensive, adaptable, and multidisciplinary educational framework to establish India as a knowledge superpower worldwide. The present study thoroughly examines the strengths, implementation prospects and problems of the education policy, also emphasizing the importance of stakeholder engagement, efficient governance and creative thinking for realizing the ambitious objective of the programme. How education policy is useful in achieving the global education agenda like Sustainable Development Goals (SDGs) and how it can help solve long-standing problems in Indian education while opening the doors to inclusive and sustainable development.

मुख्य शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा सुधार, समग्र शिक्षा, हितधारक सहयोग, सतत विकास।

Key Words: National Education Policy 2020, Education reform, Holistic education, Stakeholder collaboration, Sustainable development.

परिचय

परिवर्तन प्रकृति का एक स्थायी और निरंतर पहलू है, कोई भी समाज परिवर्तन की प्रक्रिया से अप्रभावित नहीं रहता है। भारतीय सामाजिक विकास के ऐतिहासिक विश्लेषण में प्राचीन काल से लेकर आज तक कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य परिवर्तन सामने आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो एक राष्ट्र के भीतर सरकार की शिक्षा के प्रति सोच को प्राथमिकता देती है। वैश्विक विश्वविद्यालय गुणवत्ता में भारत की घटती रैंकिंग पर हाल की चिंताओं ने सरकार को सुधार के लिए ठोस उपाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया। कस्तूरिरंगन को एक नई शिक्षा नीति तैयार करने का काम सौंपा गया था, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हुआ। इसके बाद, जुलाई 2020 में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी, जिसने भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक मौलिक बदलाव का संकेत दिया। इस मंजूरी के साथ ही संशोधित नीति उद्देश्यों के साथ संरचित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत में तीसरी ऐसी नीति है। जैसे-जैसे सामाजिक गतिशीलता विकसित होती रहती है, एक अद्यतित शिक्षा नीति की आवश्यकता तेजी से स्पष्ट होती जाती है।

29 जुलाई, 2020 को प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इक्कीसवीं सदी की प्राथमिक शिक्षा नीति के रूप में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है। यह पाँच प्रमुख स्तंभों पर जोर देता है: पहुँच, सामर्थ्य, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही, जिसका उद्देश्य समाज और अर्थव्यवस्था में पनपने के लिए निरंतर सीखने के अवसरों की तलाश करने वाले व्यक्तियों की उभरती ज़रूरतों को पूरा करना है। शिक्षा नीति संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप, सभी के लिए शीर्ष-स्तरीय शिक्षा और निरंतर सीखने के अवसरों तक पहुँच की गारंटी देने के लिए, शासन और विनियमन को शामिल करते हुए शिक्षा प्रणाली के हर पहलू का गहन पुनर्मूल्यांकन और सुधार प्रस्तावित करती है। शिक्षा नीति आधुनिक अंकीय अर्थव्यवस्था में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आने वाली पीढ़ी को आवश्यक कौशल

से लैस करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा क्षेत्रों में पर्याप्त सुधारों का प्रस्ताव करती है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक एक व्यापक संरचना प्रदान करता है, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2021 तक भारत के शैक्षिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। नीति में नामांकन दरों में महत्वपूर्ण वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक साक्षरता मानकों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, पाठ्यक्रम और शिक्षण सुधार, परीक्षा प्रक्रिया संशोधन और शिक्षक प्रशिक्षण पहल जैसे विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया गया है।

साहित्य समीक्षा

एथल व अन्य (2020) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अग्रणी शोध किया और निष्कर्ष निकाला कि उच्च शिक्षा किसी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति को आकार देने के साथ-साथ मानव व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा विभाग द्वारा सकल नामांकन अनुपात (GER) को बढ़ाया जाना सुनिश्चित हो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उच्च शिक्षा तक समान पहुँच मिल सके। शिक्षा नीति द्वारा, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, सामर्थ्य, आकर्षण और उपलब्धता बढ़ाने पर केंद्रित अभिनव उपायों के माध्यम से इन उद्देश्य को प्राप्त करना है। शिक्षा नीति ने 2030 तक की अवधि में प्राप्त करने के लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी, योग्यता-आधारित प्रवेश, छात्रवृत्ति और शोध-उन्मुख संकाय के लिए समर्थन शामिल है। उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक छात्र-केंद्रित बनने की उम्मीद है, जो विषय विकल्पों, पाठ्यक्रम विकास और मूल्यांकन विधियों में लचीलापन प्रदान करती है। शिक्षा नीति, शिक्षा के पारंपरिक तरीकों से बदलाव का प्रतीक है, जो भारतीय उच्च शिक्षा परिदृश्य में कौशल विकास, अनुसंधान अभिविन्यास और योग्यता-आधारित शिक्षा पर जोर देती है।

कल्याणी (2020) ने निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है। नीति का उद्देश्य, शिक्षा और उद्योग के

बीच एक उल्लेखनीय अंतर को पहचानना है, जिसके परिणामस्वरूप कुशल स्नातकों को बेरोजगारी या अल्परोजगार से जूझना होता है, इस विभाजन को पूर्ण करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक पाठ्यक्रम, बोर्ड परीक्षाओं पर कम जोर, विविध विषय और विषय चयन में अधिक लचीलेपन जैसी आशाजनक पहल पेश करता है, जो शिक्षा को छात्रों की रुचियों और प्राथमिकताओं के साथ अधिक निकटता से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त, अंतर्निहित प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए अंगुलि-चिह्न-विज्ञान को शामिल करना व्यक्तिगत शिक्षा के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे छात्रों को अपने विषय विकल्पों को अपने कौशल और प्रतिभा के साथ संरेखित करने की अनुमति देकर सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

कौरव व अन्य (2020) ने चर्चा की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत में शैक्षिक प्रणाली को बढ़ाने के लिए एक व्यापक खाका प्रदान करता है, जिसमें आलोचनात्मक सोच, व्यावहारिक शिक्षा और स्वदेशी भाषाओं में निर्देश पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कृषि से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवरों को विकसित करना है। नीति अंतःविषय दृष्टिकोण पेश करती है, जिससे पेशेवर डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को मानविकी का भी पता लगाने में मदद मिलती है, जो पिछली बाधाओं से हटकर है। उच्च ड्रॉपआउट दरों को संबोधित करने के लिए व्यावसायिक कौशल और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है, साथ ही अतिरिक्त लचीलेपन के लिए हस्तांतरणीय क्रेडिट बैंकों की शुरुआत की गई है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देकर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य ड्रॉपआउट दरों को कम करना और सीखने के परिणामों को बढ़ाना है। कुल मिलाकर, नीति छात्रों को आवश्यक कौशल से परिपूर्ण लैस करने, संभावित रूप से भारत के शिक्षा क्षेत्र को बदलने और इसे वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की उम्मीद करती है।

सुंदरम (2020) ने जोर देकर कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के कार्यान्वयन में रोजगार, व्यवसाय, उद्यमिता और शिक्षण में अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला को अनलॉक करने की क्षमता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति

2020 में व्यक्तियों और समुदायों दोनों को नुकसान के चक्र से बाहर निकालने की क्षमता है। विविध विषयों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करके, छात्र ज्ञान का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें समाज की जरूरतों को पूरा करने वाले स्वरोजगार सहित उत्पादक करियर विकल्प चुनने का अधिकार मिलता है। नीति सतत विकास लक्ष्य, विशेष रूप से शिक्षा से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (SDG - 4) पर विशेष जोर देती है, जो 2030 तक अन्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका को मान्यता देती है। इसके अलावा, संगीत, कला और वाद्ययंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। शिक्षा में तकनीकी प्रगति सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए दरवाजे खोलती है, जो आईटी उद्योग के महत्वपूर्ण पहलू हैं। कुल मिलाकर, यह आशा की जाती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहु-विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से समग्र विकास चाहने वाले छात्रों के लिए व्यापक रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।

सावंत व अन्य (2021) के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य इसे आधुनिक बनाना और सभी के लिए समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित है, जो भारत को वैश्विक ज्ञान नेता के रूप में देखता है। यह स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा को और अधिक लचीला, सर्वव्यापी और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए पुनर्गठन करना चाहता है। नीति शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से 2030 तक के लिए एक व्यापक कार्यान्वयन योजना निर्धारित करती है, जिसमें दृश्यमान परिवर्तनों की उम्मीद है। हालाँकि, सफल निष्पादन कार्यान्वयनकर्ताओं द्वारा चुनौतियों की समझ और समाधान पर निर्भर करता है, जिसके लिए स्वीकृति, प्रतिबद्धता और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत भारत सरकार द्वारा लगभग तीन दशकों के बाद शिक्षा नीति में पर्याप्त संशोधन के बाद एक महत्वपूर्ण कदम है। मसौदा समिति ने नीति में विविध

दृष्टिकोणों, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और हितधारकों की प्रतिक्रिया को शामिल करने का प्रयास किया है, जिसका उद्देश्य एक समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाना है जो शिक्षार्थियों को उद्योग और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे।

ठाकुर व अन्य (2021) ने तीनों राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया, जिसमें पुष्टि की गई कि भारत सरकार भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए लगातार शैक्षिक रणनीति तैयार करती है। पिछली राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों ने इसकी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और आगामी तीसरी राष्ट्रीय शैक्षिक नीति इस प्रक्षेपवक्र को और बढ़ाएगी। इस नीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन इसके परिणामों की तुलना वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्ययोजना से करके किया जाएगा। नीति की सफलता अंतर्निहित मुद्दों और बाधाओं से प्रभावी ढंग से निपटने की इसकी क्षमता पर निर्भर करती है।

वर्मा व अन्य (2021) ने निष्कर्ष निकाला कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 21वीं सदी के भारत की मांगों के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना है। यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो इस संशोधित प्रणाली में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की क्षमता है। इस नई नीति के तहत 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के दायरे में आ गए हैं। 34 वर्षों के अंतराल के बाद प्रस्तुत की गई इस नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है, जिसका विशिष्ट लक्ष्य वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।

कुमार (2022) के अनुसार भारत पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित निर्देशों को लागू करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में क्रांति लाना है। प्राथमिक लक्ष्य एक नई शैक्षिक प्रणाली स्थापित करना है जो युवाओं को सशक्त बनाती है, नवाचार और तकनीकी दक्षता के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों के

विकास को बढ़ावा देती है सभी को मूल्य-आधारित, ज्ञान-आधारित और कौशल-आधारित उच्च शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नीति शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, चुने हुए क्षेत्रों में रुचि को प्रोत्साहित करने और अधिक आरामदायक और सफल जीवन के लिए अभिनव समाधानों की खोज को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय प्रस्तुत करती है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की परिकल्पना ऐसे व्यक्तियों को तैयार करने के लिए की गई है जो बेहतर मानवीय मूल्यों, अनुशासन और आपसी सम्मान के माध्यम से एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, जो अंततः नई तकनीकों को अपनाने और बढ़ावा देने के माध्यम से सामाजिक प्रगति में योगदान करते हैं। नई शिक्षा नीति की शोध-उन्मुख प्रकृति से इन उद्देश्यों की प्राप्ति में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे प्रत्येक हितधारक एक नवप्रवर्तक में बदल जाएगा।

लुकोस व अन्य (2023) ने समीक्षा की और निर्धारित किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों के लिए कौशल-आधारित और व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता देकर शिक्षा परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। 21वीं सदी के कौशल कहे जाने वाले इन आवश्यक कौशलों में रचनात्मकता, सहयोग, बुनियादी जीवन कौशल और सामाजिक कौशल शामिल हैं, जिसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। इन आवश्यकताओं को संबोधित करके, नीति व्यावसायिक शिक्षा के बारे में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की मानसिकता को बदलने, उच्च शिक्षा और प्रतिष्ठित करियर के लिए आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। यह अनुशंसा की जाती है कि शैक्षणिक संस्थान और स्कूल अपने पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करें, इस परिवर्तन के लिए शिक्षकों को सुसज्जित करने के लिए व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से शुरुआत करें।

मंडल (2023) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का गहन विश्लेषण किया, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के ढांचे के भीतर इसके महत्व और बाधाओं का आकलन करना था। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन प्रक्रियाओं, प्रशासन, समावेशिता और निष्पक्षता सहित नीति के प्रमुख पहलुओं की गहन जांच के माध्यम से, यह शोध पत्र इसके निष्पादन से जुड़े

संभावित लाभों और चुनौतियों के बारे में व्यावहारिक अवलोकन प्रदान करता है। इस विश्लेषण के परिणाम शैक्षिक पुनर्गठन पर चल रहे विमर्श में योगदान करते हैं और नीति निर्माताओं और संबंधित पक्षों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव प्रदान करते हैं, जिससे भारत में शिक्षा के प्रक्षेपवक्र को प्रभावित किया जा सके।

वानी व अन्य (2023) ने निष्कर्ष निकाला कि केंद्र सरकार द्वारा समर्थित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। इस नीति के सफल कार्यान्वयन में देश को शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थान देने की क्षमता है। लचीलेपन और गुणवत्ता पर जोर देने के साथ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा प्रणाली को फिर से जीवंत करने और इसे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ने का वादा करती है। पारंपरिक कक्षा शिक्षण और परीक्षाओं के बोझ को कम करके, नीति देश के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता सभी स्तरों पर सुसंगत और पारदर्शी निष्पादन पर निर्भर करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : आगे का रास्ता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक कुशल स्व-नियामक प्रणाली के माध्यम से संस्थानों के लिए कम विनियमन और बढ़ी हुई स्वायत्तता की सुविधा प्रदान करती है। यह केवल शैक्षणिक डिग्री से ज्यादा जीवन कौशल और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर जोर देती है।

- प्रत्येक छात्र के लिए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक दोनों पहलुओं में समग्र विकास का समर्थन करने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षित करना। विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में, छात्रों को विभिन्न प्रकार के विषयों में से चुनने की अधिक स्वतंत्रता होगी। इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प, और व्यावसायिक कौशल शामिल होंगे, जिससे वे अपने स्वयं के अध्ययन कार्यक्रम और जीवन लक्ष्य बना सकेंगे। प्रत्येक वर्ष पेश किए जाने वाले विषयों और पाठ्यक्रमों का एक विस्तृत चयन, समग्र विकास के साथ, माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई पहचान होगी।

- ज्ञान के सभी क्षेत्रों में सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सीखने के लिए एक बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, छात्रों को विविध विषयों से जुड़ने और एक व्यापक कौशल सेट विकसित करने का मौका देती है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य व्यक्तियों को आधुनिक युग की जटिल मांगों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक बहुमुखी प्रतिभा से लैस करना है।
- सहानुभूति, सम्मान, स्वच्छता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना।
- बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करना और शिक्षा में भाषा के महत्व को पहचानना।
- संचार, सहयोग, टीमवर्क और लचीलापन जैसे जीवन कौशल विकसित करना।
- शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में तकनीक का व्यापक रूप से लाभ उठाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में तकनीक के महत्व को स्वीकार करती है और हर शैक्षिक स्तर पर इसके समावेश की वकालत करती है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाना है, साथ ही नए और आविष्कारशील सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। विविधता को अपनाना और पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और नीतियों में स्थानीय संदर्भ को शामिल करना।
- सभी शैक्षिक निर्णयों में समानता और समावेश को मौलिक सिद्धांतों के रूप में बनाए रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उन्नत मानदंड, निरीक्षण तंत्र और मान्यता संरचनाओं को शुरू करके भारत में शिक्षा के मानक में सुधार करना है। यह प्रयास यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शैक्षणिक संस्थान शीर्ष स्तर की शिक्षा प्रदान करें और छात्रों को शिक्षण वातावरण से इष्टतम लाभ हो।
- शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र के रूप में मान्यता देना, उनकी भर्ती, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना।
- शिक्षा और समग्र विकास को आगे बढ़ाने के लिए

अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डालना। शैक्षिक विशेषज्ञों से निरंतर अनुसंधान और इनपुट के आधार पर नियमित मूल्यांकन और समीक्षा करना।

- भारत के पास तुलनात्मक रूप से कम शिक्षा लागत के कारण विदेशी छात्रों और विश्वविद्यालयों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनने का अवसर है, इस प्रकार यह एक शिक्षा केंद्र के रूप में उभर रहा है।
- **छात्र प्रगति:** संस्थानों का उद्देश्य छात्रों को स्नातक स्तर से आगे उच्च शिक्षा या पेशेवर पाठ्यक्रम करने के लिए प्रेरित करना है।
- **इष्टतम शिक्षक-छात्र अनुपात:** कम शिक्षक-छात्र अनुपात बनाए रखने से छात्रों की प्रगति की नज़दीकी निगरानी की अनुमति मिलती है, जिससे शिक्षकों के बीच दक्षता बढ़ती है।
- **कक्षा में भागीदारी:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लचीलापन, जिसमें कई प्रवेश और निकास बिंदु शामिल हैं, कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, छात्रों के लिए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण (KSA) विकसित करने के लिए सहकर्मियों से सीखने और अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देता है।
- **सार्थक प्रशिक्षुता:** प्रशिक्षुता में व्यावहारिक ज्ञान की पेशकश की जानी चाहिए और शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों को केवल प्रमाणपत्र पूरा करने के बजाय मूल्यवान अनुभव प्राप्त हों।
- रटने और परीक्षा-उन्मुख शिक्षण पर वैचारिक समझ को प्राथमिकता देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान, रचनात्मकता और संचार जैसी क्षमताओं को पोषित करने के महत्व को रेखांकित करती है। यह फ़ोकस छात्रों की रोज़गार क्षमता को बढ़ाने और उन्हें लगातार विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में कामयाब होने के लिए तैयार करने की दिशा में है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है। इसके सकारात्मक पहलुओं के बावजूद, नीति कई चुनौतियों का सामना कर रही है। सबसे पहले, इसके व्यापक

दायरे में सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निवेश और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। दूसरे, नीति के लिए अनुदान में स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव है, जिससे राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (NRF) जैसी पहलों की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित तीन-भाषा फ़ॉर्मूले ने विवाद को जन्म दिया है, जिसमें संभावित भाषा थोपने और सांस्कृतिक विविधता के क्षरण की चिंताएँ हैं। शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करना एक और बाधा है, क्योंकि मौजूदा प्रणाली को विकसित शैक्षिक मांगों के साथ संरेखित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। समग्र छात्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक नई मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना करती है, विशेष रूप से संसाधन-सीमित ग्रामीण क्षेत्रों में। समावेशिता की आकांक्षाओं के बावजूद, शिक्षा में मौजूदा असमानताएँ, जिनमें लिंग, सामाजिक-आर्थिक और क्षेत्रीय विभाजन शामिल हैं, महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं। इसके अलावा, जबकि नीति निजी क्षेत्र की भागीदारी की वकालत करती है, वहीं शिक्षा क्षेत्र में संभावित व्यावसायीकरण और मौजूदा असमानताओं के बढ़ने की आशंकाएँ भी हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ते हुए, भारत के शिक्षा परिदृश्य को बदलने की इसकी क्षमता को अधिकतम करते हुए उल्लिखित चुनौतियों का समाधान करना अनिवार्य है। सबसे पहले, प्रभावी नीति निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र सहित हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत किया जाना चाहिए। शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जैसी पहलों का समर्थन करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और स्थायी वित्त पोषण तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने और संभावित विवादों को कम करने के लिए भाषा नीति के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण आवश्यक हैं। बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करना और समावेशी उपायों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना न्यायसंगत परिणाम प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक कदम हैं। इसके अलावा, शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने और निजी क्षेत्र की भागीदारी से उत्पन्न होने वाली असमानताओं को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक विनियमन और निगरानी महत्वपूर्ण है। सहयोग, नवाचार और समावेशिता को प्राथमिकता देकर, भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना कर सकता है और अधिक न्यायसंगत, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

संदर्भ

1. Aithal, P. S. and Aithal, S. (2020). Strategies for implementation of higher education towards achieving the objectives of India's National Education Policy 2020. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences*, 5(2), 283-325.
2. Wani, A.A., Manhas, K.K., & Kumar, M. (2023). Theoretical analysis of National Education Policy 2020: Challenges and way forward. *International Journal of Multidisciplinary Education and Research*, 8(1), 42-45.
3. Lukose, M. and Sharma, P. (2023). A study on the role of NEP 2020: skill development of students. *Amity International Journal of Teacher Education*, 9(1), 115-120.
4. Sawant, D.R.G. and Sankpal, D.U.B. (2021). National Education Policy 2020 and Higher Education: A Brief Review. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 9(1), 3456-3460.
5. Sondhia, R.L. (2022). A study on awareness of New Education Policy (2020) among school teachers of Jabalpur district. *International Journal of Innovative Research in Technology*, 8(9), 77-80.
6. Thakur, P and Kumar, D.R. (2021). Educational Policies, Comparative Analysis of National Education Policies and Challenges of India. *International Journal of Multidisciplinary Educational Research*, 10(3), 13-16.
7. Kalyani, P. (2020). An empirical study on NEP 2020 [National Education Policy] with special reference to its impacts on the future of Indian education system and stakeholders. *Journal of Management Engineering and Information Technology*, 7(5), 1-17.
8. Das, P., Das, G., & Burman, D. P. (2023). National Education Policy 2020: Current issues and reimagining the future of higher education. *International Journal of Indian Psychology*, 11(3), 3881-3889.
9. Mistry, D. B. (2022). Analytical review of NEP 2020. *International Journal of Multilingual Research on All Subjects*, 10(2), 9-12.
10. Sundaram, K. M. (2020). A study on National Education Policy 2020 in relation to career opportunities. *Shanlax International Journal of Economics*, 9(1), 3-67.
11. Mandal, M.A.A. (2023). A critical analysis of National Education Policy 2020: implications and challenges. *International Journal of Research Publications and Reviews*. 4(7), 1971-1978.
12. Kumar, D.A. (2022). Importance of National Education Policy-2020 in imparting education. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2), 6557-6561.
13. Jain, S., Goyal, O., & Goyal, P. (2023). Impact of NEP 2020 on higher education in India: A comparative study of selected educational institutions before and after implementation of the policy. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 11(5), 349-360.
14. Verma, D.H. and Kumar, A. (2021). India's new education policy 2020: A theoretical analysis. *International Journal of Business and Management Research*, 9(3), 302-306.

□